Daily Current Affairs
04 September 2026

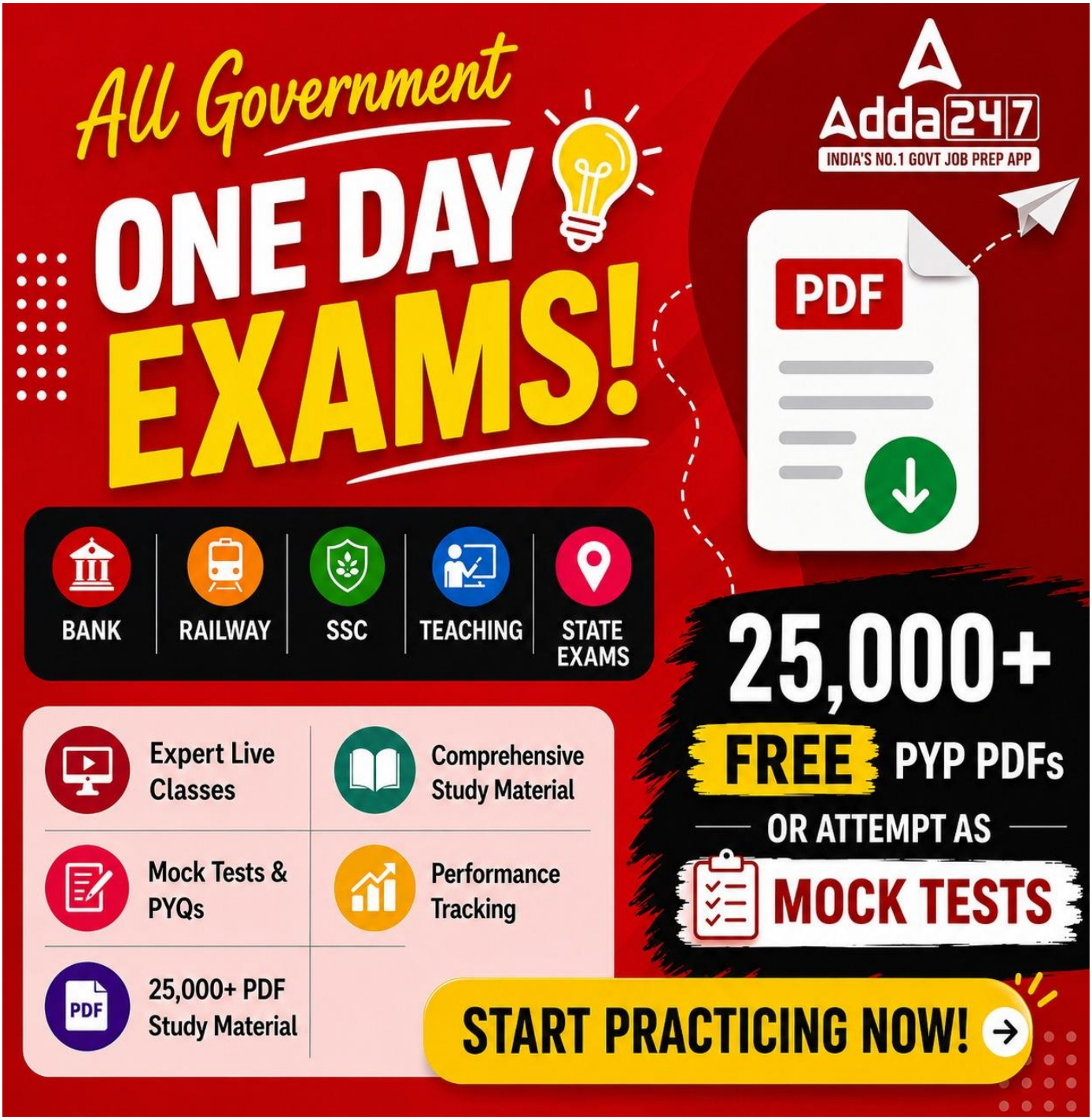

Daily Current Affairs Quiz 04 September 2026

Q1. UNCCD COP17 का विषय क्या था?
(a) जीवन के लिए भूमि
(b) भूमि बहाल करना। आशा बहाल करना।
(c) जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि बहाली
(d) एक साथ मरुस्थलीकरण का मुकाबला
Ans.(b)
Sol. सही उत्तर (B) भूमि बहाल करना। आशा बहाल करना। है
स्पष्टीकरण:
• मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP17) के 17वें सत्र के लिए आधिकारिक विषय 'भूमि बहाल करना। आशा बहाल करना।' निर्धारित किया गया था।
• यह विषय टिकाऊ भूमि बहाली प्रथाओं और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के लिए व्यापक आशा के बीच महत्वपूर्ण, अविभाज्य संबंध को रेखांकित करता है।
• UNCCD COP शिखर सम्मेलन सम्मेलन के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करते हैं, जो भूमि क्षरण का मुकाबला करने और गंभीर सूखे के प्रभावों को कम करने पर बहुपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाते हैं।
• विषय केवल क्षरण का मुकाबला करने से लेकर प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय रूप से बहाल करने के लिए एक प्रतिमान बदलाव पर प्रकाश डालता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) के अनुरूप है।
• ऐसे सम्मेलन इस बात पर जोर देते हैं कि भूमि मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत तत्व है, जिसमें हमारे कैलोरी सेवन का 99% हिस्सा होता है और यह एक बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है।
Information Booster:
• UNCCD रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप तीन 'रियो सम्मेलनों' में से एक है। अन्य दो UNFCCC (जलवायु परिवर्तन) और UNCBD (जैविक विविधता) हैं।
• UNCCD पर्यावरण और विकास को टिकाऊ भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
• भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) UNCCD द्वारा समर्थित एक मुख्य अवधारणा है, जिसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता स्थिर रहती है या बढ़ती है।
• मानक पर्यावरण विज्ञान ग्रंथ (जैसे एनसीईआरटी कक्षा 12 जीव विज्ञान - पर्यावरण के मुद्दे) मरुस्थलीकरण के गंभीर परिणामों पर जोर देते हैं, जो मुख्य रूप से अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और खराब कृषि पद्धतियों से प्रेरित हैं।
• UNCCD का उद्देश्य 2030 तक भूमि-क्षरण-तटस्थ विश्व प्राप्त करना है, जो सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 15.3 के अनुरूप है।
Additional Knowledge
• जीवन के लिए भूमि (विकल्प A): यद्यपि 'लैंड फॉर लाइफ' एक चल रहा, प्रमुख UNCCD वकालत कार्यक्रम है और टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह COP17 सम्मेलन के लिए विशिष्ट विषय नहीं था।
• जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि बहाली (विकल्प C): यह वाक्यांश मिट्टी के स्वास्थ्य को कार्बन अनुक्रमण से जोड़ने वाले एक सामान्य वैज्ञानिक औचित्य को समाहित करता है, लेकिन इस विशेष COP सत्र के लिए आधिकारिक तौर पर नामित आदर्श वाक्य नहीं था।
• एक साथ मरुस्थलीकरण का मुकाबला (विकल्प D): यह एक सामान्य पर्यावरण नारा है जिसका उपयोग अक्सर पहले के जागरूकता अभियानों (जैसे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस) में किया जाता है, लेकिन COP17 का औपचारिक विषय नहीं है।

Q2. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP17) का 17वां सत्र कहां आयोजित किया गया था?
(a) नई दिल्ली, भारत
(b) उलानबटोर, मंगोलिया
(c) शर्म अल-शेख, मिस्र
(d) रियाद, सऊदी अरब
Ans.(b)
Sol. सही उत्तर (B) उलानबटोर, मंगोलिया है
स्पष्टीकरण:
• UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP17) का 17वां सत्र मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित होने वाला है।
• मंगोलिया को मेजबान देश के रूप में चुना गया था क्योंकि यह पारंपरिक खानाबदोश आजीविका पर मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और चरम जलवायु घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों का एक स्पष्ट, वास्तविक दुनिया का केस स्टडी प्रस्तुत करता है।
• मंगोलिया के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 76% वर्तमान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जो बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन और पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से प्रेरित है।
• उलानबटोर COP17 2030 की समय सीमा से पहले मिट्टी के कटाव को रोकने और नष्ट हो चुके पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए बाध्यकारी नीतियां तैयार करने के लिए विश्व के नेताओं, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज के लिए एक रणनीतिक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
• राष्ट्र ने UNCCD के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए 'बिलियन ट्री' राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रूप से शुरू किया है।
Information Booster:
• मंगोलिया के परिदृश्य में दक्षिण में विशाल गोबी रेगिस्तान और मध्य और पूर्व में व्यापक स्टेपी घास के मैदानों का प्रभुत्व है। (क्षेत्रीय विश्व भूगोल में शामिल)।
• मंगोलिया के लिए अद्वितीय एक घटना 'दज़ुद' है—गर्मियों के सूखे के बाद आने वाली एक गंभीर कठोर सर्दी, जो लाखों पशुओं की बड़े पैमाने पर भुखमरी की ओर ले जाती है, भूमि क्षरण और गरीबी को गंभीर रूप से बढ़ाती है।
• UNCCD इस बात पर जोर देता है कि मरुस्थलीकरण से निपटना गरीबी उन्मूलन और कमजोर आबादी के लिए खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।
• COP में लिए गए निर्णयों को राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रमों (NAPs) के माध्यम से विश्व स्तर पर लागू किया जाता है, जो टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए अनुकूलित राष्ट्रीय रणनीतियां हैं।
• मंगोलिया की COP अध्यक्षता का उद्देश्य पारंपरिक पशुचारण को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के बीच जटिल संबंधों को उजागर करना है।
Additional Knowledge:
• नई दिल्ली, भारत (विकल्प A): भारत ने सितंबर 2019 में UNCCD के COP14 की मेजबानी की, जहां प्रधान मंत्री मोदी ने 2030 तक भारत के भूमि बहाली लक्ष्य को 21 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर करने की घोषणा की।
• शर्म अल-शेख, मिस्र (विकल्प C): मिस्र एक प्रमुख पर्यावरण शिखर सम्मेलन का मेजबान है (हाल ही में 2022 में UNFCCC COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है) और 2028 में भविष्य के UNCCD COP18 की मेजबानी करने वाला है।
• रियाद, सऊदी अरब (विकल्प D): सऊदी अरब को 2024 में UNCCD COP16 के मेजबान के रूप में चुना गया था, जिसमें मध्य पूर्व क्षेत्र में भूमि बहाली और सूखे के लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

Q3. UNCCD COP17 में भारत की पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने अपना पहला 'ग्रासलैंड्स और अन्य ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स (ONEs) के लिए गाइड' लॉन्च किया।
2. भारत ने बॉन चुनौती के तहत 21.76 मिलियन हेक्टेयर क्षरित और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाली के दायरे में लाया है।
3. भारत ने भूमि बहाली के लिए पर्याप्त, अनुमानित और निरंतर अंतरराष्ट्रीय वित्त का आह्वान करते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर प्रकाश डाला।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Ans.(d)
Sol. सही उत्तर (D) 1, 2 और 3 है
स्पष्टीकरण:
• कथन 1 सही है: गैर-वन पारिस्थितिक तंत्र की उपेक्षा को दूर करने के लिए, भारत ने 'ग्रासलैंड्स और अन्य ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स (ONEs) के लिए गाइड' लॉन्च किया। यह दस्तावेज़ सवाना, घास के मैदानों और बीहड़ों को 'बंजर भूमि' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक रणनीतियां प्रदान करता है।
• कथन 2 सही है: बॉन चुनौती के तहत अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, भारत ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर क्षरित और वनों की कटाई वाली भूमि को सफलतापूर्वक बहाली के तहत लाया है, जो 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर के अपने अंतिम लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
• कथन 3 सही है: COP में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संवादों के दौरान, भारत ने प्रणालीगत वित्तीय सुधारों की पुरजोर वकालत की। इसने विकसित देशों से पर्याप्त और निरंतर जलवायु और भूमि वित्त प्रदान करने का आग्रह करते हुए मॉडल के रूप में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और MoEFCC के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे अपने घरेलू नवाचारों को प्रदर्शित किया।
• सभी कथन हाल के UNCCD COP सत्रों में प्रदर्शित भारत के आधिकारिक रुख, उपलब्धियों और नीतिगत रिलीज को सटीक रूप से दर्शाते हैं।
Information Booster:
• बॉन चुनौती 2011 में शुरू किया गया एक वैश्विक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर क्षरित और वनों की कटाई वाले परिदृश्यों को बहाल करना है।
• ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) 'LiFE' (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) आंदोलन के तहत शुरू किया गया एक अभिनव बाजार-आधारित तंत्र है। यह जल संरक्षण, वनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
• सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए तैयार घरेलू और विदेशी पूंजी जुटाने के लिए जारी किए गए वित्तीय साधन हैं।
• मानक एनसीईआरटी जैविक और भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार, खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र (ONEs) अपार जैव विविधता (जैसे, शुष्क घास के मैदानों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) को आश्रय देते हैं और पशुपालक समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) भारत में UNCCD दायित्वों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

Additional Knowledge:
• केवल 1 और 2 (विकल्प A): गलत है क्योंकि कथन 3 को छोड़ना जलवायु वित्त और बाजार-आधारित पर्यावरणीय तंत्र के संबंध में COP में भारत के अग्रणी राजनयिक प्रयास को अनदेखा करता है।
• केवल 2 और 3 (विकल्प B): गलत है क्योंकि यह कथन 1 को छोड़कर, ग्रासलैंड्स और ONEs को आधिकारिक रूप से दस्तावेज करने और संरक्षित करने में भारत के अभूतपूर्व पारिस्थितिक प्रतिमान बदलाव को पहचानने में विफल रहता है।
• केवल 1 और 3 (विकल्प C): गलत है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी किए गए बॉन चुनौती लक्ष्यों के तहत भारत की मात्रात्मक, भौतिक प्रगति (21.76 Mha) को नजरअंदाज करता है।

Q4. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) को किस वर्ष अपनाया गया था?
(a) 1992
(b) 1994
(c) 1996
(d) 1998
Ans.(b)
Sol. सही उत्तर (B) 1994 है
स्पष्टीकरण:
• मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) को 17 जून, 1994 को पेरिस, फ्रांस में औपचारिक रूप से अपनाया गया था।
• इसके अपनाए जाने के बाद, सम्मेलन को अक्टूबर 1994 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और आवश्यक अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद 26 दिसंबर, 1996 को कानूनी रूप से लागू हुआ।
• UNCCD की उत्पत्ति सीधे रियो डी जनेरियो में ऐतिहासिक 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई प्रत्यक्ष सिफारिशों से हुई है।
• यह सम्मेलन विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।
• यह वर्तमान में मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है।
Information Booster:
• 17 जून, जिस दिन सम्मेलन को अपनाया गया था, उसे भूमि क्षरण के मुद्दों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व स्तर पर 'विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
• यह सम्मेलन बॉटम-अप दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोर देता है, मरुस्थलीकरण से निपटने में स्थानीय समुदायों, स्वदेशी आबादी और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
• भूगोल में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम (कक्षा 10 और 12) इस बात का विवरण देता है कि मरुस्थलीकरण मौजूदा रेगिस्तानों का प्राकृतिक विस्तार नहीं है, बल्कि जलवायु विविधताओं और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के कारण शुष्क भूमि में भूमि का क्षरण है।
• सम्मेलन प्रगति की निगरानी करने, विज्ञान-आधारित लक्ष्यों को अद्यतन करने और वित्तीय संसाधन जुटाने पर बातचीत करने के लिए नियमित रूप से कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) सत्र आयोजित करता है।
• आज तक, UNCCD में 197 पार्टियों (196 व्यक्तिगत देशों और यूरोपीय संघ) के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है।
Additional Knowledge:
• 1992 (विकल्प A): यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का वर्ष है, जहां UNCCD के लिए विचार और सिफारिश का जन्म हुआ था (एजेंडा 21 के हिस्से के रूप में), लेकिन सम्मेलन को दो साल बाद तैयार और अपनाया गया था।

• 1996 (विकल्प C): यह वह वर्ष है जब UNCCD आधिकारिक तौर पर लागू हुआ (इसके अनुसमर्थन करने वाले सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया), न कि इसके प्रारंभिक अपनाने का वर्ष।
• 1998 (विकल्प D): यह वर्ष UNCCD ढांचे को अपनाने या लागू होने के लिए कोई प्राथमिक महत्व नहीं रखता है; पहला COP वास्तव में 1997 में रोम में आयोजित किया गया था।

Q5. कौन सा देश 2028 में UNCCD COP के 18वें सत्र (COP18) की मेजबानी करेगा?
(a) भारत
(b) मंगोलिया
(c) मिस्र
(d) लक्ज़मबर्ग
Ans.(c)
Sol. सही उत्तर (C) मिस्र है
स्पष्टीकरण:
• यह आधिकारिक तौर पर तय किया गया और घोषणा की गई कि अरब गणराज्य मिस्र वर्ष 2028 में UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP18) के 18वें सत्र की मेजबानी करेगा।
• मिस्र द्वारा इस महत्वपूर्ण मरुस्थलीकरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक पर्यावरण कूटनीति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के व्यापक पैटर्न का अनुसरण करती है, विशेष रूप से हाल ही में 2022 में शर्म अल-शेख में UNFCCC COP27 की मेजबानी करने के बाद।
• UNCCD COP की मेजबानी के लिए मेजबान देश को भूमि बहाली ढांचे से संबंधित उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठकों, वैज्ञानिक समिति की समीक्षाओं और वैश्विक हितधारक संवादों की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
• मिस्र, एक ऐसा देश जहां 95% से अधिक भूमि क्षेत्र को अति-शुष्क रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कृषि (विशेष रूप से नील डेल्टा के साथ) पर भूमि क्षरण और पानी की कमी के अस्तित्व संबंधी खतरों को गहराई से समझता है।
• इस COP से 2030 भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की गंभीर रूप से समीक्षा करने की उम्मीद है।
Information Booster:
• UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज आमतौर पर द्विवार्षिक (हर दो साल में) आयोजित की जाती हैं।
• हाल के UNCCD COP पर्यावरण सम्मेलनों के बदलते फोकस को उजागर करते हैं: COP14 (2019) नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था; COP15 (2022) आबिदजान, कोटे डी आइवर में; COP16 (2024) रियाद, सऊदी अरब में; और COP17 (2026) मंगोलिया में।
• मरुस्थलीकरण के संबंध में अफ्रीका सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाद्वीपों में से एक है, विशेष रूप से साहेल क्षेत्र। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल एक प्रमुख UNCCD-समर्थित परियोजना है जो विस्तार करते सहारा रेगिस्तान को रोकने के लिए अफ्रीका की चौड़ाई में फैली हुई है।
• सहारा रेगिस्तान की प्राकृतिक सीमाएं जलवायु व्यवस्था और मानवजनित भूमि कुप्रबंधन दोनों के कारण घटती-बढ़ती रहती हैं।
• COP बैठकों के एक प्रमुख परिणाम में ग्लोबल मैकेनिज्म के लिए धन की भरपाई करना शामिल है, जो देशों को टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए संसाधन जुटाने में मदद करता है।
Additional Knowledge:
• भारत (विकल्प A): भारत ने 2019 में नई दिल्ली में UNCCD COP14 की मेजबानी की, जहां बड़े पैमाने पर भूमि बहाली लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध 'नई दिल्ली घोषणा' को अपनाया गया था।

• मंगोलिया (विकल्प B): मंगोलिया 2026 में UNCCD COP17 के लिए नामित मेजबान है, COP18 के लिए नहीं। मंगोलिया गोबी रेगिस्तान के विस्तार और अत्यधिक चराई से गंभीर मरुस्थलीकरण के खतरों का सामना कर रहा है।
• लक्ज़मबर्ग (विकल्प D): लक्ज़मबर्ग न्यूनतम प्रत्यक्ष मरुस्थलीकरण खतरों वाला एक छोटा, अत्यधिक विकसित यूरोपीय राष्ट्र है, हालांकि यह एक दाता पार्टी के रूप में भाग लेता है। यह COP18 की मेजबानी नहीं कर रहा है।